हिन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

पृष्ठ संख्या.... 2

❐ वर्ष-8 ❐ अंक-24 जयपुर, रविवार 15 दिसम्बर, 2024 ❐ एक प्रति 5 रुपये ❐ कुल पृष्ठ-4

राइजिंग राजस्थान समिट 2024 उपलब्धियों और असीम संभावनाओं के साथ सम्पन्न

जयपुर। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर अर्थनीति बनेगा तथा राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रत्येक कोने में

राजस्थान का उद्यमी मौजूद है तथा प्रत्येक राजस्थानी अब आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधान ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के प्रमुख शैक्षणिक शिक्षा आईआईटी जोधपुर, केन्द्रीय विश्व विद्यालय जैसे संस्थान में एडवांस टैक्नोलॉजी लैब को स्थापित करने में मदद करेगी। राजस्थान की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 11 प्रतिशत की विकास दर प्रदेशवासियों की मेहनत को दर्शाती है। प्रधान 11 दिसम्बर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का सफल आयोजन किया है तथा उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

राजस्थान के व्यक्ति में उद्यमिता के गुण जन्म से ही मौजूद

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान केवल पूंजी निर्माता ही नहीं बल्कि नॉलेज बेस्ड इकोनोमी है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स सहित सभी विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को जॉब सीकर्स से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। लेकिन राजस्थान के व्यक्ति को उद्यमिता सिखाने की जरूरत नहीं है उसमें यह खूबी जन्म से ही होती है। उन्होंने कहा कि जैसे खाड़ी देश विश्व अर्थनीति के केन्द्र हैं, वैसे ही भविष्य में जयपुर-जैसलमेर दुनिया के अर्थनीति के केन्द्र बनना तय हैं तथा यह समिट इसको दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधान ने कहा कि इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू साइन हुए हैं जोकि एक प्रोग्रेसिव पहल है। दुनिया में ऊर्जा की खपत अमरीका और चीन के बाद भारत में सर्वाधिक होती है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ग्रीन एनर्जी तथा न्यू एनर्जी भी सृजित करेगा तथा राजस्थान इस क्षेत्र में लीडर पोजिशन पर आ गया है। यहां हुए निवेशों से लोगों को संसाधन मिलेंगे, आय का सृजन होगा तथा आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी जिससे पूरा राज्य विकास की दौड़ में अग्रणी बन सकेगा। प्रधान ने कहा कि पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में 'आर' राजस्थान को माना जाता था लेकिन अब वही 'आर' राजस्थान राइजिंग की तरफ बढ़ रहा है।

राजस्थान नवाचार व निवेश का बना नया केंद्र-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राइजिंग समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेगी तथा अगले वर्ष 11 दिसंबर को इन सभी एमओयू के जमीन पर उतरने की कार्यवाही की समीक्षा कर जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन 2026 में फिर से होगा। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरपूर राजस्थान में उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने की क्षमता है। राजस्थान नवाचार व निवेश आकर्षण के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए हैं।

उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने की कई पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति, पांच नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन, रीको द्वारा 8 औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए हम अगले तीन साल में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीआई टैग वाले उत्पाद गांव से ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी विरासत भी' विजन को साकार करेंगे।

राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 सहित 10 नीतियों से निवेश को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जीएसडीपी में करीब 25 प्रतिशत योगदान दे रहा है। साथ ही, निर्यात में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये उद्योग समावेशी आर्थिक विकास, इनोवेशन और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 एवं अन्य 9 नीतियां जारी की हैं।

नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए नई निर्यात नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'निर्यात वृद्धि, सर्व समृद्धि' में विश्वास करती है जो निर्यातकों की समृद्धि और उनके सशक्तीकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान में नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से हमने कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 लागू कर वोकल फोर लोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह नीति हमारी पारंपरिक कला के संरक्षण और विकास में भी मददगार होगी।

मुख्यमंत्री ने किया सभी का धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने एतिहासिक आयोजन के लिए सभी मंत्रिगण, निवेशकों, उद्योगपतियों, अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समिट में विशेषज्ञों द्वारा आए नए आइडियाज से राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल एवं मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार राजस्थान राइजिंग के साथ रिलायबल एवं रिसेप्टिव भी है जो खुद को रिफ्लेक्ट करना भी जानता है। मोदी जी के राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन सत्र में दिए गए वक्तव्य से टीम राजस्थान को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान पहले केवल पर्यटन के लिए जाना जाता था। लेकिन अब इस समिट के सफल आयोजन से प्रदेश उद्योग क्षमताओं के लिए भी जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान लक्ष्य की प्राप्ति में यह समिट मील का पत्थर साबित होगा। हमने बजट में राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हम ब्रांडिंग, प्रमोशन तथा टूरिस्ट सर्किट विकसित करने पर फोकस कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों के कारण आज का दिन राज्य ही नहीं देश के लिए एतिहासिक अवसर है। यह समिट राज्य की क्षमता, आकांक्षाओं और संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विश्व भर के विभिन्न देशों में रोड शो किए गए जिनमें राज्य में निवेश के अवसर उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की मंशा को दिखाया गया। इस समिट का सफल आयोजन यह दिखाता है कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों और उपक्रमों के एग्जीबिटर बूथ का जायजा लिया। शर्मा ने बिल्डिंग ए सिक्योर नेशन बूथ पर आधुनिक हथियारों का निरीक्षण किया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के बूथ पर 3 डी आईवीआर तकनीक के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक की माइंस का वर्चुअल टूर किया। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आई स्टार्ट राजस्थान बूथ पर रोबोटिक डॉग का रिमोट से संचालन भी किया। वे उत्तर पश्चिम रेलवे के बूथ पर भी पहुंचे और भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिंकटेक, धूत संगमरमर, हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र और एंबेसी ऑफ डेनमार्क के एग्जीबिटर बूथ का भी दौरा किया। इस दौरान वर्ल्ड बैंक के कंट्री हैड ऑगस्ट तानो कुआमे, राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य, अधिकारीगण, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा सहित बड़ी संख्या में एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े उद्यमी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया उद्घाटन

समिट के उद्घाटन सत्र में 9 दिसम्बर को जयपुर स्थित जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि आज हम ग्लोबल विजन और ग्लोबल इंपैक्ट पर काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। सरकार औद्योगिक प्रगति के लिए 'होल ऑफगवर्नमेंट एप्रोच' पर समन्वित रूप से एक साथ काम करते हुए हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रही है। सबके प्रयास की इस भावना से ही हम सब मिलकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाएंगे। भारत आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, उसे लेकर दुनियाभर के निवेशकों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी भारत दुनिया की 11वीं इकोनोमी था। लेकिन बीते 10 वर्षों में हमने 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनोमी बनने का सफर तय किया है। इस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था का आकार, कुल निर्यात और एफडीआई भी करीब दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने बीते दस साल में आधारभूत ढांचे पर खर्च भी करीब 2 ट्रिलियन से बढ़ाकर 11 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री ने समारोह स्थल में कन्द्री पैवेलियन एवं अन्य स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग की कार्यप्रणाली भी समझी। आरम्भ में मुख्यमंत्री ने चूरू के शिल्पकार द्वारा चंदन की लकड़ी से तैयार तलवार प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी अभिव्यक्ति यां हैं। उन्होंने साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया।

संपादकीय

साइबर क्राइम से निजी जानकारी-सुरक्षा को खतरा

इनसे बचाव के लिए कदम उठाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए रोकथाम प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को लगातार लागू करने, निगरानी करने और अपग्रेड करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। विदेशी विरोधियों, आतंकवादियों और रोजमर्रा के घोटालेबाजों के बीच, साइबर हमले ज्यादा चालाक और ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे हैं वर्तमान युग तकनीकी व साइबर विकास का है, प्रौद्योगिक क्रांति का है। अनेक कार्य तकनीक की सहायता से सुगम हो चुके हैं। सभी कार्य आसानी से घर बैठे सम्पन्न हो जाया करते हैं। बाजार की पहुंच भी घर तक सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन इसी क्रम में अपराधियों की पहुंच भी सीधे घर तक हो गई है। पलक झपकते ही अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे डालते हैं। भारत जहां विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ अपराधी भी अपना तकनीकी विकास कर धड़ल्ले से लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। तकनीक में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध ने लोगों की निजी जानकारी और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। साइबर अपराध के कई प्रकार हैं, चाहे वो जानकारी चोरी करना हो, हैकिंग हो, फिशिंग हो, वायरस फैलाना हो, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, फर्जी बैंक कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना व साइबर बुलिंग इत्यादि हो। इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि चिंताजनक है। जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं मन की बात जैसे देशव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से चिंता व्यक्त कर इससे बचने हेतु आगाह कर रहा हो, सोचिए वो कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों से आग्रह है कि जब भी कोई कॉल आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। इस क्रम को अपनाने की आवश्यकता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में साइबर क्राइम के 65893 मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। साल 2021 में 52974 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें भी करीब 65 फीसदी मामले धोखाधड़ी के ही हैं। यानी 65893 मामलों में 42710 धोखाधड़ी के मामले हैं।

जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 12 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष, सुप्रबल जनसेवाश्री जनरल अशोक राज सिगडेल को उनकी सराहनीय सैन्य कौशल और भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण सम्बंधों को और आगे बढ़ाने में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की।

सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुभारंभ

जयपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनको प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका संवर्धन का कार्य किया जाता है। जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के द्वारा हैंडलूम, हेंडीक्राफ्ट, एवं खाद्य गतिविधियों में पारंपरिक रूप से कार्य किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने के प्रयासों के तहत शनिवार को सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 14 दिसम्बर को वर्चुअल किया गया। यह मेला 14 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक संचालित किया जाएगा।

सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले में देश के लगभग सभी राज्यों के भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग के 250 से अधिक उत्पादों एवं क्षेत्रीय शिल्पकारों द्वारा विविध और समृद्ध विरासत को एक छत के नीचे देखने और क्रय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस आयोजन में क्षेत्रवार मंडप स्थापित किए गए हैं जिससे प्रत्येक राज्य अपनी अनूठी सांस्कृतिक कलाकृतियों को एक समर्पित स्थान पर प्रदर्शित कर रहा है। देश के लगभग समस्त प्रदेशों के 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य अपने उत्पादों को प्रदर्शित एवं विक्रय का कार्य कर रहे है। मेले में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ एवं उन्नत तकनीक से बने हुए अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस आयोजन में सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाते हुए अधिकांश राज्यों के फूड स्टाल्स से सजे काउंटर आगंतुकों को पूरे देश के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं जो देश की विविधता को दर्शाती एक अनूठी पाक कला को प्रदर्शित करता है। मेले में ग्रामीण हस्त निर्मित उत्पादों के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। फूड कोर्ट में विभिन्न राज्यों की महिलाओं द्वारा स्वादिष्ट व्यंजन बनाये जाते हैं जिसका लुत्फ यहां आने वाले आगंतुक ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान का चूरमा दाल बाटी, सिक्किम के मोमोज, चौमिन, ठुक्पा, सेल रोटी एवं आलू दम, आसाम के नारियल लड्डू, काला चावल खीर, तिल पेठा, कतली पेठा, पश्चिम बंगाल के पेटी सेपता, लूची करी, तेलंगाना के वेज बिरयानी, इडली डोसा, जम्मू कश्मीर के कहवा, मध्यप्रदेश के आलू परांठा, मेथी परांठा, गरदु की टिक्की, पोहा जलेबी, गुजरात के मक्की की रोटी, उड़द की दाल, दाल भात, हिमाचल प्रदेश के सिदडु राजमा, हिमाचल प्रदेश के ड्राइ फरूट सिदडु असकाली रजना, तमिलनाडु के बेटरूट मल्ट, केरेट मल्ट, बग्गी, बोंडा, आंध्र प्रदेश के ओर्गेनिक जगेरी पाउडर, हेमोग्लोबिन लड्डू, उत्तराखंड के मँडुआ का गोल गप्पा, स्प्रिंग रोल्ल, केरेला से वडा, बोंडा मुख्य व्यंजन है।

यह मेला पर्यटन के पीक मौसम के दौरान आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी चलाया जा रहा है जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के आगंतुकों की एक बड़ी संख्या के आकर्षित होने की उम्मीद है। यह आयोजन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने अनूठे दस्तकारी उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। सौंदर्यता से ओतप्रोत भिन्न-भिन्न प्रदेशों की संस्कृति, परिधान, भाषा, एवं पारंपरिक उत्पादों का बेजोड़ नमूना इस सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले में देखने को मिलता है। यह अपनी तरह का ऐसा आयोजन है जिससे सभी 250 से अधिक जीआई टैग उत्पाद एक ही स्थान पर अपना आकर्षण बिखेरते नजर आ रहे हैं। ये मेले महिलाओं को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को विक्रय करने का एक उन्नत मंच उपलब्ध करवा रहा है जहाँ महिलाए अपनी कला को प्रदर्शित कर अपने उत्पादों का श्रेष्ठ मूल्य प्राप्त कर रही है। राष्ट्रीय राज सखी मेला 2024 मे 2000 रूपये से अधिक खरीददारी करने वाले ग्राहकों को सुपर लक्की ड्रॉ ग्रैन्ड प्राइज के तहत ब्रांड न्यू कार एवं लक्की बायर अवॉर्ड के तहत प्रथम प्राइज एक्टिवा, द्वितीय प्राइज लैपटॉप एवं तृतीय प्राइज एप्पल आई फोन उपहार जीतने का सुनहरा मोका मिलेगा।

बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव सम्पन्न

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन जयपुर और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम 14 दिसम्बर को जारी किए गए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर महेन्द्र शांडिल्य, दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद पर संदीप लुहाडिया व डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर गजराज सिंह राजावत निर्वाचित हुए। गौरतलब है कि 13 दिसम्बर को वोट डाले गए थे। वहीं हाईकोर्ट बार महासचिव पद पर रमित पारीक, दी बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव पद पर मनीष गगरानी माहेश्वरी और डिस्ट्रिक्ट बार महासचिव पद पर नरेन्द्र सिंह राजावत विजयी हुए।

हाईकोर्ट बार चुनाव समिति की मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल के अनुसार अध्यक्ष पद पर विजित महेन्द्र शांडिल्य को 1664 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजीव सोगरवाल ने 1453 मत प्राप्त किए। वहीं महासचिव पद के लिए रमित पारीक को 1480 और दीपेश शर्मा को 1147 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष के दो पदों पर बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा, कोषाध्यक्ष गोविन्द शर्मा, संयुक्त सचिव सौरभ दुबे, सांस्कृतिक सचिव सुनीता मीणा, पुस्तकालय सचिव हिम्मत सिंह जादौन, संयुक्त पुस्तकालय सचिव राजेन्द्र सिंह निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि अधिवक्ता संजू सैनी, चैन सिंह राठौड, कृपा कुमारी, मोबिना खान, रामबाबू शर्मा, ताराचंद शर्मा, गजेन्द्र व्यास और शत्रुघ्न शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।

दी बार एसोसिएशन जयपुर- अध्यक्ष पद पर रहा कड़ा मुकाबला

दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसमें संदीप लुहाड़िया अध्यक्ष पद पर 29 वोटों से विजयी रहे। लुहाड़िया को 1386 और प्रतिद्वंदी सोमेश शर्मा को 1357 वोट मिले। मतगणना के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं महासचिव पद पर मनीष गगरानी माहेश्वरी ने उमेश चौधरी को 465 मतों से पराजीत कर जीत दर्ज की। मनीष को 1259 और उमेश चौधरी को 794 मत मिले। उपाध्यक्ष के दो पदों पर रमेश चन्द्र शर्मा व बीना कुमारी निर्वाचित हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी राम मनोहर शर्मा के अनुसार संयुक्त सचिव पद पर श्रीकृष्ण शर्मा, कोषाध्यक्ष के पद पर योजन शर्मा, सांस्कृतिक सचिव पद पर अंकित कपूर व उप कोषाध्यक्ष पद पर आकाश कपूर विजयी रहे। वहीं डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन चुनाव अधिकारी नरेन्द्र सिंह के अनुसार उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए दलीप सिंह व प्रेम प्रकाश शर्मा, सांस्कृतिक सचिव पद पर दीक्षा आर्य, संयुक्त सचिव पद पर संतोष कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं संगठन सचिव पद पर नंदकिशोर कुमावत, पुस्तकालय सचिव पद पर भानूप्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार शर्मा, उप कोषाध्यक्ष पद पर प्रियंका गौड और उप पुस्तकालय सचिव पद पर बीनू शर्मा ने जीत दर्ज कराई। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए सुमन कंवर, जगदीश शर्मा, संजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित, अनिता रावत, प्रमोद कुमार शर्मा, दीपक शर्मा, रामस्वरूप सैनी, संदीप कुमार, सोमेश शर्मा और योगेश अग्रवाल विजयी रहे।

रन फॉर विकसित राजस्थान-2024, ऊर्जा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

जयपुर। राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 12 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे कोटा में महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम से निकली रन फॉर विकसित राजस्थान-2024 को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऊर्जा मंत्री भी मैराथन में दौडे। यह मैराथन स्टेडियम से निकलकर अग्रसेन चौराहा, किशोर सागर तालाब, राजकीय संग्रहालय, जेडीबी कॉलेज होती हुई पुनः महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम में आकर समाप्त हुई। मैराथन में जनप्रतिनिधि, जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी सहित जिला स्तरीय अधिकारी, कॉलेज-यूनिवर्सिटी के छात्र, खिलाडी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, पुलिस, आरएसी, होमगार्ड के जवान सहित गैर सरकारी संगठनों एवं आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

अंतरिक्ष क्षेत्र में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अंतरिक्ष विजन 2047 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। ये प्रयास तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं। सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए हैं। इन सुधारों के एक हिस्से के रूप में सरकार ने विभिन्न संस्थाओं जैसे आईएन एंड स्पेस, इसरो और एनएसआईएल की भूमिकाओं को रेखांकित किया है। सरकार ने स्पेस विजन 2047 की घोषणा की है, जिसके तहत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) की स्थापना और 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस दिशा में चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है- गगनयान फ्लैगऑन मिशन और 2028 तक बीएएस प्रथम मॉड्यूल की स्थापना, 2032 तक अगली पीढ़ी के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) (पुनः प्रयोज्य कम लागत वाले लॉन्च व्हीकल) का विकास, 2027 तक चंद्रयान-4, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने और चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही 2028 तक वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम), जो शुक्र की सतह और उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करेगा। विभाग ने अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण मिशनों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें अंतरिक्ष विजन 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में विकास के कई क्षेत्रों को एकीकृत किया गया है। रोडमैप के प्रमुख कदम इस प्रकार हैं- 2028 तक प्रथम मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) का प्रक्षेपण, 2035 तक पूर्ण बीएएस की स्थापना, 2040 तक चंद्रमा पर लैंडिंग। सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 जारी की है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को अंतरिक्ष गतिविधियों में शुरू से अंत तक उनकी भागीदारी को बढ़ाकर समान अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया गया, जिससे विभिन्न अंतरिक्ष क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जा सका। अंतरिक्ष स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए आईएन एंड स्पेस के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

देश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल एवं स्मारकों का संरक्षण

नई दिल्ली। विश्व धरोहरों स्थलों की सूची में नए विरासत स्थलों को शामिल किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। विश्व धरोहर सूची में भारत के 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल सहित 43 स्थल अब तक शामिल हैं। यूनेस्को के परिचालन दिशानिर्देश 2023 के अनुसार प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित केवल एक स्थल को सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। वर्ष 2024-25 के लिये 17वीं-19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली एवं रणनीति दर्शाने वाले 12 किलों और दुर्गों के मराठा सैन्य परिदृश्य को शिलालेख प्रक्रिया हेतु यूनेस्को को सौंपा गया है।

अभी विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के मंदिर सहित 56 स्थल शामिल हैं। यूनेस्को के प्रचालन दिशानिर्देशों के आधार पर विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने पर विचार किया जाता है। वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2013 का 18) में कहा गया है कि भारत के 92 संरक्षित स्मारक गायब हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम

से किए गए बाद के सर्वेक्षण से पता चला है कि 18 संरक्षित स्मारक और स्थल संरक्षण की अच्छी स्थिति में नहीं हैं। सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के क्षेत्रीय कार्यालयों ने पता लगाया कि तेजी से शहरीकरण के कारण स्मारकों पर दबाव एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, निजी सुरक्षा गार्ड और सीआईएसएफ के माध्यम से स्मारकों की देखभाल और निगरानी की जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं। एएसआई द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय संरक्षण नीति में संरक्षित स्मारकों की स्थिति का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण का प्रावधान है। मुख्य रूप से, एएसआई के उप-मंडलों और मंडलों के अधिकारी स्मारकों का नियमित निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय निदेशालय और मुख्यालय के अधिकारी भी स्मारकों की स्थिति का निरीक्षण और निगरानी करते हैं।

सर्दी के मौसम में शीत लहर से पशुओं को बचाएं

जयपुर । सर्दी के मौसम में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाता है। ऐसे में पशुओं को भी शीतलहर से बचाना जरूरी होता है, वरना पशुधन बीमार पड़ सकता है। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि राज्य में ठंड बढ़ने के साथ कुछ जगहों पर शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इतने कम तापमान से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। खासकर दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्?पादन पर ठंड का बहुत असर पड़ता है। अधिक ठंड के कारण दुधारू पशु अक्सर जल्दी बीमार पड़ते हैं और दूध देना कम कर देते हैं। इसके कारण पशुपालकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वे सर्दी के मौसम में अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उन्हें ठंड से बचाएं, रात के समय पशुओं को खुले में न बांधें। उन्हें कंबल या जूट के बोरों से ढंककर रखें। दिन के समय संभव हो तो उन्हें धूप में रखें। उन्होंने कहा कि ठंड के समय में पशुओं के आहार का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। उनके खुराक मे सूखा चारा, मोटा अनाज, सरसों की खल आदि की अधिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं को सप्ताह में दो बार गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। उन्होंने पशुशाला को साफ और सूखा रखने की सलाह भी पशुपालकों को दी।

उन्होंने कहा कि पशुओं के आश्रय स्थल एवं पशु शालाओं में समय-समय पर डिसइनफेक्टेंट का छिड़काव करके उन्हें विसंक्रमित भी करना चाहिए। पशुपालन मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा पशुओं की देख भाल को लेकर समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं पशुपालक उन निर्देशों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय या उप केंद्र में संपर्क करें।

बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

नई दिल्ली। सरकार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले खतरों और लत जैसे संभावित नुकसानों से अवगत है। भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन गेम की लत जैसी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, आईटी अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) को अधिसूचित किया है।

आईटी नियम, 2021 ने सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित विभिन्न मध्यस्थों पर उस सूचना के संबंध में विशिष्ट सावधानी बरतने के दायित्व डाले हैं, जिसे प्लेटफॉर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा नहीं किया जाना है। मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी ऐसी सूचना को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित न करें जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो। मध्यस्थों को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी सूचना को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई या किसी भी ऐसी सूचना के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शामिल है, जो अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित या प्रोत्साहित करती है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2021 को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय ने 10 दिसंबर, 2021 को बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर अभिभावकों और शिक्षकों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में संकेत दिया गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने से गंभीर गेमिंग की लत लग जाती है जिसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाता है। इसने आगे चेतावनी दी है कि बिना किसी प्रतिबंध और आत्म-सीमा के ऑनलाइन गेम खेलने से कई खिलाड़ी आदी हो जाते हैं और अंततः गेमिंग डिसऑर्डर का निदान किया जाता है। अभिभावकों और शिक्षकों को एडवाइजरी को व्यापक रूप से प्रसारित करने और बच्चों को मानसिक और शारीरिक तनाव से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग नुकसानों पर काबू पाने में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें शिक्षित करने की सिफारिश की गई है।

इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2020 को सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को ऑनलाइन गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन के बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उन्हीं का पालन किया जाए। दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

किसी भी गेमिंग विज्ञापन में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट/स्टेटिक तथा ऑडियो/वीडियो फॉर्म में एएससीआई कोड के अनुरूप डिस्कलेमर होना चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है तथा यह व्यसनकारी हो सकता है। विज्ञापनों में गेम को वैकल्पिक रोजगार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी नहीं दर्शाना चाहिए कि गेमिंग गतिविधि करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से दूसरों की तुलना में अधिक सफल है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मीडिया को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और/या इन प्लेटफॉर्म को छः तरीके से दर्शाने वाले किसी भी ऐसे उत्पाद/सेवा के विज्ञापनों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने को कहा गया है। ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर न दिखाएं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है। एमएचए ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अलग-अलग तंत्र हैं। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 29 नवम्बर को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

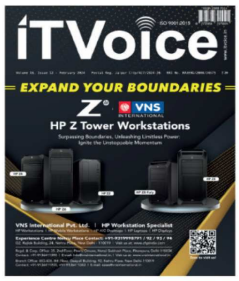

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com